[2020] 13 एस. सी. आर 1230

टाइटी एलियास जॉर्ज कुरियन

बनाम

डिप्टी रेंज वन अधिकारी

समीक्षा याचिका (आपराधिक) संख्या 593/2018

में (आपराधिक अपील संख्या 758/2018)

09 दिसंबर, 2020

[न्यायाधिपति अशोक भूषण और न्यायाधिपति इंदु मल्होत्रा]

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972। धारा 2, 9, 11, 12, 39 ए, 49 ए, 51; अनुसूची I का भाग II-प्रत्यर्थी से जब्त किया गया कछुआ-उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी गई - आयोजित: निर्णय दिनांक 16.05.18 को वापस ले लिया गया - धारा 9 अनुसूची I, II, III और IV के तहत किसी भी जंगली जानवर के शिकार पर प्रतिबंध लगाती है, धारा 11 और 12 के तहत दिए गए प्रावधानों को छोड़कर - तथ्यों पर, जब्त किया गया कछुआ इसमें शामिल नहीं है भाग II, अनुसूची I और इसे जब्ती के दूसरे दिन पहले ही मुक्त कर दिया गया था, इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने

आपराधिक कार्यवाही - आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 482 को रद्द करने में कोई त्रुटि नहीं की।

पुनर्विक्षा याचिका को अनुमति देते हुए और अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने आयोजित किया: वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 9 धारा 11 और 12 के तहत दिए गए प्रावधानों को छोड़कर अनुसूची I, II, III और IV के तहत किसी भी जंगली जानवर के शिकार पर रोक लगाती है। अनुसूची I से IV तक, यह अधिनियम, 1972 की धारा 51 के तहत दंड को आमंत्रित करने वाला अपराध बन जाता है। पशु चिकित्सा सर्जन द्वारा दिए गए पत्र का अवलोकन इंगित करता है कि पशु चिकित्सा सर्जन ने कछुए की पहचान 'इंडियन फ्लैप शेल (लिसेमी का पंक्टाटा)' के रूप में की है, जबकि कछुआ जो अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के भाग II में शामिल है, वह "भारतीय नरम-खोल वाला कछुआ (लिसेमिस पंक्टाटा पंक्टाटा)" है। लिस्सेमिस पंक्टाटा एक ऐसी प्रजाति है जिसकी लिसेमिस पंक्टाटा इन्फ्रास्पेसिस है। हालाँकि लिसेमिस पंक्टाटा भाग II में शामिल है अधिनियम की अनुसूची I में, हालाँकि, जो कछुआ जब्त किया गया है वह वह नहीं है जो अनुसूची I के भाग II में शामिल है। वर्तमान मामले के तथ्यों में, प्रथम दृष्टया, जब्त किया गया कछुआ अनुसूची I भाग II में शामिल नहीं है। और कछुए को उसकी जब्ती के दूसरे दिन ही मुक्त कर दिया गया था, उच्च न्यायालय ने वन्य जीवन अपराधों के लिए दर्ज

आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में कोई त्रुटि नहीं की। उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा आधार नहीं मिला। [पैरा 12-14][1233-एच; 1234-ए-डी]

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार : 2018 की आपराधिक अपील संख्या 758 में 2018 की पुनर्विक्षा याचिका (आपराधिक) संख्य 593/2018 2018 की आपराधिक अपील संख्या 758 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दिनांकित 16.05.2018 के निर्णय और आदेश से।

अभिलाष एम. आर., मोहम्मद सादिक टी. ए., निशे राजन शोंकर, अधिवक्ता उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

न्यायाधिपति अशोक भूषण

1. हमने याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अभिलाष एम.आर. और प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री निशे राजेन शोंकर को सुना है।

2. हमें दिनांक 16.05.2018 के फैसले की समीक्षा करने के लिए पर्याप्त आधार मिलता है। इस न्यायालय का दिनांक 16.05.2018 का आदेश वापस लिया जाता है। समीक्षा याचिका स्वीकार की जाती है।

3. यह अपील केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 16.11.2017 के फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने 2016 की सीसी संख्या 706 में कार्यवाही को रद्द करके प्रतिवादी द्वारा दायर 2017 की आपराधिक एमसी संख्या 2720 की अनुमति दी है। उप रेंज वन अधिकारी इस फैसले से व्यथित हैं। यह अपील हाई कोर्ट में आई है.

4. मामले के तथ्य संक्षेप में हैं:

25.07.2016 को प्रतिवादी, टिट्टी उर्फ जॉर्ज कुरियन से एक कछुआ रानी फॉरेस्ट फ्लाइंग स्क्वॉयर रेंज स्टाफ द्वारा जब्त किया गया था। करुंबनाकुलम. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 2, 9, 39 ए, 49 ए और 51 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। वन पदाधिकारी द्वारा आरोप पत्र समर्पित किया गया. कछुए को जब्त करने के बाद, उसे पहचान के लिए पशु चिकित्सा सर्जन के पास भेजा गया, जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 26.07.2016 द्वारा निरीक्षण के दौरान कछुए की पहचान "इंडियन फ्लैप शेल" के रूप में की, वैज्ञानिक नाम "लिसेमिस पंक्टाटा" है। न्यायालय ने 27.07.2016 को कछुए को मुक्त करने का निर्देश दिया।

5. प्रतिवादी-अभियुक्त ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था कि भारतीय फ्लैप शैल कछुआ जिसे जब्त किया गया था, उसे वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के भाग II की

अनुसूची I में शामिल नहीं पाया गया था, इसलिए, उस प्रजाति के कछुए का ऐसा कब्ज़ा आमंत्रित नहीं किया जाएगा। अभियुक्त के विरुद्ध कथित अपराध. उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट था कि जब्त किया गया कछुआ कछुए की उस प्रजाति का नहीं है जो अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के भाग II में शामिल है, आवेदन की अनुमति दी और आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित होकर यह अपील उप रेंज वन अधिकारी द्वारा दायर की गई है।

6. अपीलकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि क्या भारतीय नरम-खोल कछुए (लिसेमिस पंक्टाटा पंक्टाटा) और भारतीय फ्लैप शैल कछुए (लिसेमिस पुंटाटा) दो अलग-अलग प्रजातियां हैं या एकल प्रजाति का हिस्सा हैं या बाद की उप-प्रजाति विशेषज्ञ साक्ष्य का मामला है और होना चाहिए केवल परीक्षण के तहत निर्णय लिया गया और उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन को अनुमति देने में त्रुटि की।

7. प्रतिवादी के विद्वान वकील के आदेश का समर्थन करते हुए उच्च न्यायालय का तर्क है कि जब जब्त किए गए कछुए का उल्लेख वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची में नहीं है, तो किसी भी अपराध को दर्ज करने का कोई अवसर नहीं है, और अपराधों के पंजीकरण को उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से रद्द कर दिया गया है, जिसके साथ किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि कछुए को

25.07.2016 को जब्त किया गया था और 27.07.2016 को मुक्त कर दिया गया था और आगे की जांच के लिए उपलब्ध नहीं होने के कारण पशु चिकित्सा सर्जन की रिपोर्ट केवल देखने के लिए सामग्री है और वैज्ञानिक नाम जो पशु चिकित्सा सर्जन द्वारा दिया गया था उसे जगह नहीं मिलती है अधिनियम, 1972 की अनुसूची में।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

9. उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के आपराधिक एम. सी. को अनुमति देने के लिए निम्नलिखित कारण दिए गए हैंः

> "4. अधिनियम की अनुसूची I के भाग II के अवलोकन पर, ऐसा लगता है कि आइटम नंबर 8 इंडियन सॉफ्ट शैल टर्टल (लिसेमिस पंक्टाटा पंक्टाटा) है। इस मामले में वरिष्ठ पशुचिकित्सक द्वारा रेंज अधिकारी, एरुमेली को जारी किए गए प्रमाण पत्र से पता चलता है कि इस मामले में जब्त किया गया कछुआ इंडियन फ्लैप शैल टर्टल (लिसेमिस पंक्टाटा) है। उपरोक्त अनुसूची में इंडियन फ्लैप शैल टर्टल नामक प्रजाति शामिल नहीं है।जब विचाराधीन कछुआ भारतीय सॉफ्ट शैल कछुए से संबंधित नहीं है, तो उसे

पकड़ना या उसके कब्जे को वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में, याचिकाकर्ता के खिलाफ एरुमेली वन रेंज के ओआर नंबर 5/2016 के आधार पर न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट II, कंजिरापल्ली के सीसी नंबर 706/2016 में सभी आगे की कार्यवाही रद्द की जा सकती है।"

10. 25.07.2016 को कछुए की जब्ती के बाद अगले दिन उप रेंज अधिकारी द्वारा कछुए की पहचान के लिए पशु चिकित्सा सर्जन को संदर्भित किया गया था। निरीक्षण के बाद पशुचिकित्सक ने दिनांक 26.07.2016 को रेंज अधिकारी को निम्नलिखित आशय का पत्र लिखा:

"से,

डॉ. अनिल कुमार टी वरिष्ठ पशुचिकित्सक

बी.वी. एससी एवं ए.एच. पशु चिकित्सा अस्पताल रजि. क्रमांक 1329,

एरुमेली.

रेंज अधिकारी एरुमेली,

एरुमेली.

विषय: प्रजाति की पहचान

संदर्भ: डिप्टी रेंज अधिकारी दिनांक 26.07.2016

उपरोक्त संदर्भ के अनुसार दिनांक 26.07.2016 को कछुआ परिवार से संबंधित एक कछुए को पहचान के लिए लाया गया था, और निरीक्षण करने पर पाया गया कि कछुआ इंडियन फ्लैप शेल है और वैज्ञानिक नाम "लिसेमीज़ पंक्टाटा" है और इसलिए यह प्रमाणित है।

26-07-2016

एरुमेली"

11. पशु चिकित्सक ने कछुए की पहचान 'इंडियन फ्लैप शेल' और वैज्ञानिक नाम 'लिसेमीज पंक्टाटा' के रूप में की।मद संख्या 8, अनुसूची I भाग II निम्नलिखित प्रभाव से हैः

"8. भारतीय नरम कवच वाला कछुआ (लिसेमी का पंक्टाटा)।"

12. अधिनियम, 1972 की धारा 9 अनुसूची I, II, III और IV के तहत किसी भी जंगली जानवर के शिकार को प्रतिबंधित करती है, सिवाय इसके कि धारा 11 और 12 तहत प्रावधान किया गया है। धारा 11 और 12 वे प्रावधान हैं जहां मुख्य वन्यजीव वार्डन की अनुमति से शिकार की अनुमति है।यदि कोई व्यक्ति अनुसूची I से IV में शामिल किसी भी जंगली जानवर का शिकार करता है, तो यह अधिनियम, 1972 की धारा 51 के तहत जुर्माना लगाने वाला अपराध बन जाता है।

13.पशु चिकित्सक द्वारा ऊपर निकाले गए पत्र के अवलोकन से संकेत मिलता है कि पशु चिकित्सक ने कछुए की पहचान 'भारतीय फ्लैप शेल (लिसेमी का पंक्टाटा)' के रूप में की है, जबकि कछुआ जो अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के भाग II में शामिल है, 'भारतीय सॉफ्ट-शेल्ड कछुआ (लिसेमी का पंक्टाटा)' है।"लिसेमीस पंक्टाटा एक प्रजाति है जिसमें से लिसेमीस पंक्टाटा इन्फ्रास्पेशिस है।यद्यपि लिसेमी का पंक्टाटा अधिनियम की अनुसूची I के भाग II में शामिल है, लेकिन जिस कछुए को जब्त किया गया है वह वह नहीं है जो अनुसूची I के भाग II में शामिल है। वर्तमान मामले के तथ्यों में, इसके बावजूद, जब्त किए गए कछुए को अनुसूची I भाग II में शामिल नहीं किया गया है और कछुए को जब्त किए जाने के दूसरे दिन पहले ही रिहा कर दिया गया है, उच्च न्यायालय ने वन्यजीव अपराधों के लिए दर्ज आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

14. हम उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए अच्छा आधार नहीं पाते हैं जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है। वर्तमान मामले के तथ्यों पर, अपील खारिज कर दी जाती है।

दिव्य पांडे

अपील खारिज कर दी गई और पुनर्विचार याचिका की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।